

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 03-01-26



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 03 Jan, 2026

Edition : International Table of Contents

पेज 02 पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन I: भारतीय समाज	कैसे भाषा के मुद्दे ने असम के सबसे अस्थिर संघर्षों में से एक को जन्म दिया
पेज 06 पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन II: शासन / प्रारंभिक परीक्षा	शहरी-ग्रामीण भागीदारी के साथ स्वच्छता को फिर से तैयार करना
पेज 06 पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन III: भारतीय अर्थव्यवस्था / प्रारंभिक परीक्षा	अविश्वसनीय विकल्प विकास पैदा करने वाला पूंजीगत व्यय राजकोषीय लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है
समाचार में पाठ्यक्रम: प्रारम्भिक परीक्षा	सिरकीर मलकोहा
समाचार में पाठ्यक्रम: प्रारम्भिक परीक्षा	आयुष के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना
पेज 06 : संपादकीय विश्लेषण पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन III: पर्यावरण	कचरे से भरे शहरी भारत को बदलना

पेज 02 : सामान्य अध्ययन I : भारतीय समाज

असम में 1961 का सिलचर भाषा आंदोलन स्वतंत्रता के बाद के भारत में भाषाई राजनीति से जुड़े सबसे हिंसक प्रकरणों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। समकालीन दक्षिण एशिया में प्रकाशित एक हालिया अकादमिक अध्ययन इस प्रकरण पर यह तर्क देने के लिए फिर से विचार करता है कि संघर्ष एक अपरिहार्य जातीय संघर्ष नहीं था, बल्कि विशिष्ट राजनीतिक निर्णयों, औपनिवेशिक विरासतों और उदार शासन की विफलताओं का परिणाम था। 19 मई, 1961 को सिलचर में प्रदर्शनकारियों पर हुई गोलीबारी, जिसमें 11 नागरिक मारे गए थे, दक्षिणी असम, विशेष रूप से बराक घाटी में भाषाई चेतना को आकार दे रही है।

How language issue led to one of Assam's most volatile conflicts

Rahul Karmakar
GUWAHATI

Decades after blood was spilt on the streets of southern Assam's Silchar, a new academic study examines how language, power and identity converged to produce one of the State's most volatile conflicts.

The study, published in *Contemporary South Asia*, analyses the 1961 violence to argue that the crisis was not inevitable but the result of political choices, policy failures and deep-seated historical anxieties.

It contends that language in Assam has never been merely a means of communication but has functioned as a marker of belonging and, at times, a trigger for violence.

The authors of the study are Md. Chingiz Khan of

the Centre for Comparative Religions and Civilisations at Jamia Millia Islamia, New Delhi, Ravi Shankar of the School of Global Affairs at B.R. Ambedkar University, Delhi, and Bharti Shokeen of Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner, Rajasthan.

The study traces the flashpoint to 1961, when the Assam government amended its Official Language Act to recognise Assamese as the sole official language, while allowing limited use of Bengali in parts of the Barak Valley. The decision triggered widespread protests across the region.

Firing by security forces at demonstrators in Silchar left 11 people dead on May 19, 1961, a moment that remains deeply etched in the collective memory of the

Barak Valley.

The study argues that reducing the episode to an "Assamese versus Bengali" conflict obscures its deeper complexity. Assam, it notes, has long been a multilingual and multi-ethnic society, home to diverse communities, whose coexistence was disrupted by rigid language policies.

Colonial policy

"An intersectional approach, considering temporality, ethnicity, region, culture, and politics, offers a more nuanced understanding [of the issue]. Assam's identity has been shaped by centuries of migration, cultural exchange, and layered histories, making rigid categorisations reductive," the study observes.

The study underlines the decisive role of colonial

Study revisits 1961 Silchar violence to examine how policy, identity and power shaped linguistic conflict

policies in shaping linguistic hierarchies. British administrators classified and ranked languages through censuses and surveys, transforming fluid identities into rigid categories.

The imposition of Bengali as the language of administration in 19th century Assam marginalised Assamese speakers in courts and government employment. When Assamese later regained official status, the balance shifted, fuelling resentment among Bengali speakers, particularly in Bengali-majority regions such as Cachar.

According to the study, language became closely tied to access to power. Official recognition translated into employment opportunities, control over land records and political influence. Communities that felt excluded came to view language policy as an existential threat.

In Cachar, where Bengali speakers formed an overwhelming majority, the enforcement of Assamese was perceived as cultural domination. In the Brahmaputra Valley, concessions to Bengali speakers were seen as undermining Assamese identity.

The study notes that the violence of 1961 reflected both popular anger and institutional failure, with the Centre and the Assam government underestimating the depth of the crisis. Interim measures such as the

Shastri Formula failed to address underlying tensions. Political parties were divided, bureaucracies were paralysed, and sections of the media, particularly newspapers published from Calcutta, were accused of aggravating the situation.

The study rejects the notion that the movement was communal in nature. Protesters on all sides included Hindus, Muslims and tribal groups, underscoring that language solidarity often cut across religious lines.

The authors conclude that the fault lines exposed in 1961 continue to shape contemporary debates around citizenship, belonging and indigeneity, particularly in the context of the National Register of Citizens and the Citizenship (Amendment) Act.

पृष्ठभूमि और मुख्य मुद्दे

शक्ति के रूप में भाषा, सिर्फ संचार नहीं

- असम राजभाषा अधिनियम (1960-61), जिसने बराक घाटी में बंगाली को सीमित रियायतों के साथ असमिया को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया, ने भाषा को राजनीतिक शक्ति और आर्थिक अवसर के निर्धारक में बदल दिया।
- आधिकारिक भाषा की स्थिति ने सीधे सरकारी नौकरियों, प्रशासन, भूमि रिकॉर्ड और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक पहुंच को प्रभावित किया।

भाषाई संघर्ष की औपनिवेशिक जड़ें

- ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने 19 वीं शताब्दी के असम में बंगाली को प्रशासनिक भाषा के रूप में थोप दिया, जिससे असमिया बोलने वालों को हाशिए पर डाल दिया गया।
- औपनिवेशिक जनगणना और भाषाई वर्गीकरण ने पहले की तरह पहचान को कठोर कर दिया, जिससे कठोर पदानुक्रम बन गए।
- स्वतंत्रता के बाद अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना, इस पदानुक्रम के उलटने से बंगाली भाषी आबादी के बीच नया असंतोष पैदा हुआ, खासकर कछार में।

'असमिया बनाम बंगाली' बाइनरी से परे

- अध्ययन में संघर्ष को एक साधारण भाषाई प्रतिद्वंद्विता तक सीमित करने के प्रति चेतावनी दी गई है। असम ऐतिहासिक रूप से बहुभाषी और बहु-जातीय रहा है।
- हिंदू, मुस्लिम और आदिवासी समुदायों को शामिल करते हुए विरोध आंदोलन धार्मिक रेखाओं से परे हैं, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि भाषा-आधारित लामबंदी अक्सर सांप्रदायिक पहचान को पीछे छोड़ देती है।

संस्थागत और राजनीतिक विफलता

- केंद्र और राज्य सरकारों दोनों ने भाषा नीति में शामिल भावनात्मक और भौतिक दांव को कम करके आंका।
- शास्त्री फॉर्मूले जैसे अस्थायी समझौतों ने सतही स्तर की मांगों को संबोधित किया, लेकिन संरचनात्मक चिंताओं को हल करने में विफल रहे।
- राजनीतिक विखंडन, नौकरशाही जड़ता और मीडिया सनसनीखेज ने तनाव को और बढ़ा दिया।

समकालीन प्रासंगिकता

- 1961 में उजागर हुई खामी रेखाएं असम में नागरिकता, स्वदेशीता और अपनेपन पर वर्तमान बहसों में गूंजती रहती हैं।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को लेकर चल रहे विवादों से पता चलता है कि भाषा, पहचान और प्रवासन कैसे आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं।
- यह प्रकरण एक संघीय और सांस्कृतिक रूप से बहुलवादी राजनीति के भीतर बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण की सीमाओं को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष

1961 की सिलचर हिंसा दर्शाती है कि भाषाई संघर्ष शायद ही कभी सहज होते हैं; वे ऐतिहासिक विरासत, असमान शक्ति संरचनाओं और नीतिगत गलत अनुमानों से आकार लेते हैं। अध्ययन का अंतर्विभाजक दृष्टिकोण संवेदनशील, समावेशी भाषा नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जो विविधता को खतरे के बजाय एक ताकत के रूप में पहचानते हैं। भारत के संघीय लोकतंत्र के लिए, सबक स्पष्ट है: स्थायी एकता एकरूपता पर नहीं, बल्कि समायोजन, संवाद और स्तरित पहचान के सम्मान पर निर्भर करती है।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: चर्चा करें कि कैसे औपनिवेशिक प्रशासनिक नीतियों ने असम में भाषाई पहचान को सख्त करने में योगदान दिया। इन विरासतों ने स्वतंत्रता के बाद के संघर्षों को कैसे आकार दिया? (150 शब्द)

पेज 06 : सामान्य अध्ययन II : शासन / प्रारंभिक परीक्षा

2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) ने सार्वभौमिक शौचालय कवरेज को प्राथमिकता देकर स्वच्छता के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक निर्णायक बदलाव को चिह्नित किया। 12 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण और सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित करने के साथ, इस कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य और गरिमा परिणाम दिए। हालाँकि, जैसे-जैसे भारत एसबीएम (ग्रामीण) चरण II में परिवर्तित हो रहा है, ध्यान बुनियादी ढांचे के निर्माण से स्थिरता, विशेष रूप से मल कीचड़ के प्रबंधन की ओर बढ़ गया है। लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे महाराष्ट्र में अभिनव शहरी-ग्रामीण भागीदारी स्वच्छता शासन की इस अगली सीमा को संबोधित कर रही है।

Recasting sanitation with urban-rural partnerships

When the Swachh Bharat Mission ('Clean India Mission') was launched in 2014, its vision was both simple and transformative; to ensure that every household in India had access to a toilet. In just a decade, this vision has become reality. More than 12 crore household toilets have been built in rural India, and every village has declared itself Open Defecation Free (ODF). This achievement has improved public health, reduced indignities faced by women and vulnerable groups, and marked a turning point in India's development journey.

Focus on waste management

Yet, the success of the sanitation mission has also revealed the next frontier. Toilets are only the starting point. The real challenge lies in managing the resultant faecal waste. In most rural households, septic tanks and pits serve as the primary form of containment. Over time, these fill up and must be desludged at regular intervals. Without safe systems for collection, transport, and treatment, the gains of the ODF movement risk being undermined. It is this challenge that defines the transition to Swachh Bharat Mission (Grameen), or SBM-G, Phase II, with its focus on ODF Plus.

ODF Plus goes beyond toilet construction to ensure the sustainability of outcomes through solid and liquid waste management, behavioural change, and safe sanitation service chains. The progress has been encouraging. As of October 2025, more than 5.68 lakh villages, nearly 97% of India's total, have been declared ODF Plus. But faecal sludge management remains one of the most critical gaps in the sanitation chain, especially in peri-urban and rural areas.

Maharashtra has been at the forefront of

Aasim Mansuri

is Principal Researcher and Center Head-Strategy, Center for Water and Sanitation, CRDF-CEPT University

Dhruv Bhavsar

is Principal Researcher and Center Head, Center for Water and Sanitation, CRDF-CEPT University

Upasana Yadav

is Senior Program Lead, Center for Water and Sanitation, CRDF-CEPT University

Kasturi Joshi

is Program Lead, Center for Water and Sanitation, CRDF-CEPT University

Jinal Chheda

is Senior Research Associate, Center for Water and Sanitation, CRDF-CEPT University

The model in Satara district in Maharashtra is an innovative experiment

experimenting with innovative approaches to address this gap. The State has invested in more than 200 faecal sludge treatment plants in urban areas and encouraged co-treatment in 41 sewage treatment plants. These facilities are a backbone of treatment infrastructure to cities, but the challenge lies in extending their benefits to the villages that surround them. It is here that urban-rural partnerships show great promise.

At the gram panchayat level

In Satara district, Maharashtra, such a partnership was put into practice. Satara city's faecal sludge treatment plant, with a capacity of 65 kilo litres a day (KLD), was operating below full capacity. Recognising this, four villages, Jakatwadi, Songaon, Kodoli, and Degaon, have been brought under an arrangement that will allow them to access the city's treatment plant.

Their septic tanks, often never desludged or emptied only at exorbitant rates by informal operators, will be serviced at regular intervals and in a safe way. A private service provider is to be engaged by the gram panchayats, under a contract, to provide scheduled desludging services every five years.

The costs will be recovered through a modest sanitation tax levied by the gram panchayats, ensuring affordability and accountability. A formal agreement between the Satara Panchayat Samiti and the Satara Municipal Council will allow authorised desludging vehicles from the gram panchayats to access the faecal sludge treatment plant and treat the sludge at no cost, making the arrangement sustainable and mutually beneficial.

But not every village can be linked to a treatment system of a city. Some will have to treat

their waste independently. An example is Mayani, a large village in Khatav taluka. With the high demand for desludging services, the gram panchayat has agreed to introduce scheduled desludging every five to seven years, managed by either a private operator or local self-help groups.

In addition, Mayani has been selected for the development of a cluster-level faecal sludge treatment plant under the SBM-G, designed to serve around 80 surrounding villages. This approach shows that rural clusters can pool resources to develop standalone treatment infrastructure that meets their needs, while remaining financially and technically viable.

The demonstration of urban-rural linkages and the standalone faecal sludge management business model in Satara district will promote the adoption and the institutionalisation of safe, sustainable sanitation services across rural Maharashtra. It also aims to show that sustaining the gains of ODF and effectively integrating faecal sludge management into rural sanitation require strong collaboration between urban and rural governments, private and public actors, and citizens and institutions.

A model that can be scaled up

If scaled up, such models have the potential to transform not only villages in Maharashtra but also rural communities across the country. By doing so, India can ensure that its sanitation gains are not only celebrated today but can be sustained for generations to come. The true measure of Swachh Bharat will not only be the toilets built but also the systems created to manage them – systems that protect peoples' health, preserve the environment, and uphold the dignity that this mission set out to achieve.

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

स्थिरता तक पहुंच से

- शौचालय केवल पहला कदम है; मल कीचड़ के सुरक्षित संग्रह, परिवहन और उपचार के बिना, स्वच्छता जोखिम उलट जाती है।
- ओडीएफ प्लस पर एसबीएम-जी चरण II का जोर स्वच्छता के लिए एक जीवनचक्र दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो व्यवहार परिवर्तन के साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को एकीकृत करता है।

मल कीचड़ प्रबंधन (FSM) क्रिटिकल गैप के रूप में

- ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में, सेप्टिक टैंक और गड्ढे हावी हैं, लेकिन गंदगी अनियमित, महंगी और अक्सर असुरक्षित होती है।

- अनौपचारिक ऑपरेटर और उपचार सुविधाओं की कमी पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है, मिट्टी और भूजल को दूषित करती है।

शहरी-ग्रामीण भागीदारी: महाराष्ट्र मॉडल

- शहरी मल कीचड़ उपचार संयंत्रों (एफएसटीपी) में महाराष्ट्र के निवेश और सीवेज उपचार संयंत्रों में सह-उपचार ने अधिशेष उपचार क्षमता का निर्माण किया है।
- सतारा में, शहर के आसपास के गांवों को ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच औपचारिक समझौतों के माध्यम से कम उपयोग किए गए शहरी एफएसटीपी से जोड़ा गया है।
- अनुसूचित मलत्याग, ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता कर, और शहरी उपचार सुविधाओं तक अधिकृत पहुंच सामर्थ्य, जवाबदेही और स्थिरता सुनिश्चित करती है।

विकेंद्रीकृत और क्लस्टर-आधारित समाधान

- सभी गांवों को शहरों से नहीं जोड़ा जा सकता है। मायनी गांव का उदाहरण एक क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां कई गांव स्टैंडअलोन एफएसटीपी बनाने के लिए संसाधनों को एकत्रित करते हैं।
- इस तरह का विकेंद्रीकरण 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के तहत सहकारी संघवाद और स्थानीय स्वशासन के सिद्धांतों के अनुरूप है।

शासन और नीति महत्व

- यह मॉडल ग्रामीण और शहरी संस्थानों, सार्वजनिक और निजी अभिनेताओं और समुदायों के बीच प्रभावी अभिसरण को प्रदर्शित करता है।
- यह एक बार की संपत्ति निर्माण से सेवा वितरण मॉडल में बदलाव पर भी प्रकाश डालता है, जो दीर्घकालिक विकास परिणामों के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत की स्वच्छता यात्रा अधिक जटिल लेकिन निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है। महाराष्ट्र के अनुभव से पता चलता है कि ओडीएफ लाभ को बनाए रखने के लिए ग्रामीण-शहरी निरंतरता में संस्थागत नवाचार, वित्तीय व्यवहार्यता और सहकारी शासन की आवश्यकता होती है। मापनीय साझेदारी और विकेंद्रीकृत समाधानों के माध्यम से मल कीचड़ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि स्वच्छता सुधार न केवल प्रतीकात्मक उपलब्धियां हैं, बल्कि टिकाऊ प्रणालियां हैं जो लंबी अवधि के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और मानव गरिमा की रक्षा करती हैं।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: ग्रामीण भारत में मल कीचड़ प्रबंधन (FSM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ग्रामीण घरों में सेप्टिक टैंक और गड्ढे प्रमुख नियंत्रण प्रणाली हैं।
2. सुरक्षित सफाई और उपचार की कमी शौचालय निर्माण के सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ को नकार सकती है।
3. एफएसएम मुख्य रूप से एक शहरी स्वच्छता चिंता का विषय है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसकी सीमित प्रासंगिकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर : a)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: शहरी-ग्रामीण भागीदारी भारत के स्वच्छता क्षेत्र में एक व्यवहार्य शासन मॉडल के रूप में उभर रही है। विकेंद्रीकृत सेवा वितरण और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में उनकी भूमिका की जांच कीजिए। (150 शब्द)

पेज 06 : सामान्य अध्ययन III: भारतीय अर्थव्यवस्था / प्रारंभिक परीक्षा

दिसंबर 2025 का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह ₹1.74 लाख करोड़ का है, जो भारत सरकार के सामने आने वाले राजकोषीय स्थान को रेखांकित करता है। बजट 2025 में हाल ही में घोषित जीएसटी दर युक्तिकरण और आयकर राहत की पेजभूमि में, डेटा एक क्लासिक व्यापक आर्थिक दुविधा को उजागर करता है: राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों का पालन करते हुए सार्वजनिक निवेश के माध्यम से विकास को कैसे बनाए रखा जाए। यह लेख भारत की वर्तमान राजकोषीय नीति के केंद्र में इस "अविश्वसनीय विकल्प" को दर्शाता है।

मुख्य मुद्दे और विश्लेषण

कर राहत के लिए मौन राजस्व प्रतिक्रिया

- दरों में कमी के बावजूद दिसंबर में जीएसटी राजस्व नवंबर की तुलना में मामूली अधिक रहा।
- यह आर्थिक वास्तविकता को दर्शाता है कि कर कटौती तुरंत उच्च खपत में तब्दील नहीं होती है; परिवार अक्सर बचत या ऋण में कमी को प्राथमिकता देते हैं, खासकर अनिश्चित व्यापक आर्थिक स्थितियों में।
- बजट 2025 में आयकर में बदलाव के बाद भी इसी तरह का पैटर्न देखा गया, जहां अल्पकालिक राजस्व की भरपाई अभी तक मांग-आधारित वृद्धि से नहीं हुई है।

बजट के राजस्व पक्ष पर जोर

- ₹13.9 लाख करोड़ (अप्रैल-नवंबर 2025) का कुल टैक्स राजस्व वर्ष-दर-वर्ष 3.4% कम है, जो राजस्व उछाल संबंधी चिंताओं को दर्शाता है।
- तंबाकू पर उच्च उत्पाद शुल्क और जीएसटी और पान मसाला पर उपकर जैसे अतिरिक्त उपायों से अगले वित्त वर्ष में ही परिणाम मिलेंगे, जो मौजूदा वित्त वर्ष में सीमित राहत प्रदान करेंगे।

पूंजीगत व्यय बनाम राजस्व व्यय की गतिशीलता

- पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) 28% बढ़कर ₹6.58 लाख करोड़ हो गया, जो सरकार की विकास-उन्मुख रणनीति की पुष्टि करता है।
- वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसी प्रतिबद्ध देनदारियों के प्रभुत्व वाले राजस्व व्यय में मामूली वृद्धि हुई 2.1% पर।
- हालांकि, राजस्व व्यय सीमित लचीलापन प्रदान करता है, जिससे पूंजीगत व्यय आसान हो जाता है - हालांकि आर्थिक रूप से महंगा - समायोजन के लिए लक्ष्य यदि राजकोषीय दबाव तेज हो जाता है।

कम मुद्रास्फीति और नॉमिनल जीडीपी का प्रभाव

- लगातार कम थोक मुद्रास्फीति (औसत -0.08%) नाममात्र जीडीपी वृद्धि को कम करती है।

Unenviable choice

Growth-generating capital expenditure can affect fiscal targets

The Goods and Services Tax (GST) revenue of ₹1.74 lakh crore in December 2025 confirms just how narrow the government's fiscal policy space is. The December data reflect the economic activity in November, the second month under the new, reduced GST rates. December's revenues were marginally higher than the ₹1.7 lakh crore collected in November. This was expected. Any belief that the rate reductions would lead to an immediate and sustained increase in demand, and hence GST collections, was pure optimism. In reality, people are more likely to use that extra money to pad up savings or pare down debt, with increased consumption a more medium-term outcome. This happened following the income-tax rejig in Budget 2025 too, when the government effectively exempted people earning up to ₹12 lakh a year from income-tax. The GST and income-tax decisions were both welcome relaxations. However, at least for this year, they are going to cause the government more pain than gain. The most recent data on the government's accounts reflect this. Total tax revenue stood at ₹13.9 lakh crore at the end of November 2025, 3.4% lower than in the same period of 2024-25. On the other hand, the Centre's capital expenditure stood at ₹6.58 lakh crore in the April-November 2025 period, 28% higher than in the same period of the previous year. This jump in capital expenditure was balanced out by a much slower growth in revenue expenditure of 2.1%. However, of the two types of spending, the government has much less discretion over revenue expenditure, which comprises expenses such as salaries, pensions and interest on loans. These cannot be kept subdued for long.

The government has valiantly tried to bolster its earnings through the new excise and GST rates on tobacco products, not to mention the health and security cess on the manufacture of pan masala. However, since all these new rates and cesses will come into effect only on February 1, their full benefit will be felt only in the next financial year. Yet, the troubles for the government's finances do not end there. The remarkably low levels of wholesale inflation this year – averaging -0.08% so far – have also meant that the size of the nominal GDP would likely be smaller than initially budgeted. This means that several ratios pegged to it, most pertinently the fiscal deficit and debt-GDP, would automatically come in larger than earlier estimated. The Centre has displayed commendable fiscal discipline over the last few years. However, this year, it has placed before itself the unenviable choice of either pulling back on growth-generating capital expenditure, or risking missing its fiscal targets.

- यह यांत्रिक रूप से राजकोषीय घाटे से जीडीपी और ऋण-से-जीडीपी जैसे प्रमुख राजकोषीय अनुपातों को खराब करता है, भले ही वास्तविक आर्थिक गतिविधि लचीली बनी रहे।
- नतीजतन, राजकोषीय समेकन कागज पर कमजोर दिखाई देता है, जिससे नीतिगत गतिशीलता बाधित होती है।

नीति दुविधा

- पूंजीगत व्यय को वापस खींचने से मध्यम अवधि के विकास, निजी निवेश भीड़-इन और रोजगार सृजन को कम करने का जोखिम होता है।
- हालांकि, उच्च पूंजीगत व्यय के साथ बने रहने से राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से चूकने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे संभावित रूप से बाजारों और रेटिंग एजेंसियों को परेशान किया जा सकता है।

निष्कर्ष

वर्तमान राजकोषीय स्थिति दर्शाती है कि ध्वनि व्यापक आर्थिक प्रबंधन में अक्सर आदर्श परिणामों के बजाय प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के बीच चयन करना शामिल होता है। पूंजीगत व्यय पर भारत का हालिया जोर विकास-आधारित समेकन के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता को दर्शाता है, लेकिन कम राजस्व और कम मुद्रास्फीति ने राजकोषीय स्थान को कम कर दिया है। आगे की चुनौती उत्पादक सार्वजनिक निवेश की रक्षा करते हुए राजकोषीय अनुशासन में विश्वसनीयता बनाए रखने में है - एक ऐसा संतुलन जो मध्यम अवधि में भारत के विकास पथ की स्थिरता को निर्धारित करेगा।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का आर्थिक विकास पर अधिक गुणक प्रभाव पड़ता है।

1. पूंजीगत व्यय सीधे राजकोषीय घाटे को जोड़ता है लेकिन मध्यम अवधि में ऋण स्थिरता में सुधार करता है।
2. राजकोषीय दबाव के दौरान राजस्व व्यय में कमी की तुलना में पूंजीगत व्यय में कमी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर : a)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: हाल के राजकोषीय रुझान विकासोन्मुखी पूंजीगत व्यय को बनाए रखने और राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों का पालन करने के बीच एक समझौता दर्शाते हैं। कम कर राजस्व और कम मुद्रास्फीति के संदर्भ में इस दुविधा का विश्लेषण करें। (150 शब्द)

समाचार में: प्रारंभिक परीक्षा

उत्तरकाशी जिले ने हाल ही में सिरकीर मलकोहा को पहली बार देखे जाने की सूचना दी है, जो आमतौर पर उत्तराखंड के मैदानी इलाकों से जुड़ी एक प्रजाति है। यह अवलोकन हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता प्रलेखन और प्रजातियों के वितरण की गतिशीलता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।



सिरकीर मलकोहा के बारे में

- सामान्य नाम: सिरकीर मलकोहा /
- वैज्ञानिक नाम: टैकोकुआ लेशेनाल्टी
- परिवार: कुकुलिडे (कोयल परिवार)

विशिष्ट जैविक विशेषता

- कई कोयल प्रजातियों के विपरीत, सिरकीर मलकोहा ब्रूड परजीवीवाद का अभ्यास नहीं करता है; यह अपना घोंसला बनाता है और अपने चूजों को स्वतंत्र रूप से पालता है। इस सुविधा को अक्सर अन्य कोयल से अलग करने के लिए प्रारंभिक-आधारित प्रश्नों में हाइलाइट किया जाता है।

वितरण और आवास

भौगोलिक सीमा:

- उप-हिमालयी भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से वितरित
- बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान और राजस्थान में छिटपुट रूप से भी पाया जाता है

पर्यावास वरीयता:

- झाड़ियाँ और खुले, पतले जंगल
- पहाड़ी इलाकों का पक्ष लेता है लेकिन आम तौर पर समुद्र तल से 1,500 मीटर से नीचे होता है

उत्तरकाशी रिकॉर्ड का महत्व:

- संभावित ऊंचाई सीमा विस्तार या सूक्ष्म आवास अनुकूलन को इंगित करता है, जो जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक बदलावों के संदर्भ में प्रासंगिक है।

शारीरिक विशेषताएं

- लंबाई: 42-44 सेमी

आलूबुखारा:

- ऊपरी भाग: समृद्ध जैतून-भूरा
- अंडरपार्ट्स: हल्का छाया, अक्सर पीले रंग के साथ
- चोंच: पीले रंग की नोक के साथ विशिष्ट रूप से घुमावदार लाल चोंच

पैर: ग्रे

यौन द्विरूपता:

- अन्यमनस्क; नर और मादा एक जैसे दिखाई देते हैं

व्यवहार:

- बेहद शांत और मायावी, जो दृश्य अपेक्षाकृत दुर्लभ बनाता है

विशेष अनुकूलन

ज़ाइगोडैक्टाइल फीट:

- दो पैर की उंगलियां आगे और दो पीछे
- शाखाओं पर मजबूत पकड़ और जमीन पर कुशल गति की सुविधा प्रदान करता है
- प्रारम्भिक एमसीक्यू के लिए प्रासंगिक एक प्रमुख शारीरिक विशेषता

आहार

मुख्य रूप से कीटभक्षी, पर खिलाना:

- छोटी छिपकलियाँ
- कीड़े
- कभी-कभी जामुन और बीज

संरक्षण की स्थिति

- IUCN रेड लिस्ट: कम से कम चिंता
- इसकी स्थिर संरक्षण स्थिति के बावजूद, इस तरह के रेंज-एक्सटेंशन रिकॉर्ड एवियन जैव विविधता निगरानी और क्षेत्रीय पारिस्थितिक आकलन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: सिरकीर मलकोहा (सिरकीर मलकोहा) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह कोयल परिवार से संबंधित है लेकिन ब्रूड परजीवीवाद का अभ्यास नहीं करता है।
2. यह आमतौर पर 2,000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर घने सदाबहार जंगलों में पाया जाता है।
3. इसमें जाइगोडेक्टाइल पैर होते हैं, जिसमें दो पैर की उंगलियां आगे की ओर और दो पीछे की ओर होती हैं।
4. यह विशेष रूप से फलों और बीजों पर फ्रीड करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 1, 2 और 3
- (c) केवल 2 और 4
- (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: a)

समाचार में: प्रारंभिक परीक्षा

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने आयुष के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के बारे में संसद को जानकारी दी, जिसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के वैश्विक पदचिह्न को बढ़ाना है।



Central Sector Scheme for Promotion of International Co-operation (IC) in Ayush

योजना के बारे में

प्रकार: केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

नोडल मंत्रालय: आयुष मंत्रालय

कवरेज: आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी

समर्थन की प्रकृति: वित्तीय और संस्थागत सहायता:

- आयुष दवा निर्माता
- आयुष सेवा प्रदाता
- शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान
- मुख्य फोकस: आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सेवा में भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करना।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य है:
- चिकित्सा की आयुष प्रणालियों के बारे में वैश्विक जागरूकता और स्वीकृति को बढ़ावा देना।
- आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष के लिए हितधारकों के साथ बातचीत और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना।
- आयुष ज्ञान प्रणालियों के प्रचार के लिए विशेषज्ञों और सूचनाओं के अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान का समर्थन करना।
- विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना के माध्यम से शिक्षाविदों और अनुसंधान को बढ़ावा देना।

योजना के प्रमुख घटक

1. विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान

- आयुष विशेषज्ञों, पेशेवरों और सरकारी अधिकारियों के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रम।
- विदेशों के साथ ज्ञान-साझाकरण और संस्थागत सहयोग।

2. वैश्विक आउटरीच के लिए प्रोत्साहन

- वित्तीय प्रोत्साहन:
 - आयुष दवा निर्माता
 - उद्यमी
 - आयुष अस्पताल और संस्थान
- उद्देश्य: अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, रोड शो और प्रचार कार्यक्रमों में भागीदारी।

3. अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकास

- निम्नलिखित उद्देश्यों के उद्देश्य से गतिविधियों के लिए समर्थन:
 - बाजार पहुंच
 - आयुष प्रणालियों की ब्रांडिंग
 - विदेशों में नियामक सुविधा।

4. प्रवासी आयुष अवसंरचना

- की स्थापना:
 - विदेशों में आयुष सूचना प्रकोष्ठ।
 - विदेश में आयुष स्वास्थ्य केंद्र / संस्थान।
- विदेशों में मौजूदा आयुष केंद्रों को मजबूत करना।

5. अंतर्राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति कार्यक्रम

- आयुष पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विदेशी नागरिकों के लिए छात्रवृत्ति/फेलोशिप:
 - आयुर्वेद
 - योग
 - यूनानी
 - सिद्ध
 - होम्योपैथी
- भारत में प्रमुख आयुष संस्थानों में किए गए पाठ्यक्रम।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : आयुष के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की योजना के तहत, निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी
2. विदेशों में आयुष स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना
3. आयुष उपचार के लिए घरेलू बीमा कवरेज

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

पेज : 06 : संपादकीय विश्लेषण

Recasting sanitation with urban-rural partnerships

When the Swachh Bharat Mission ('Clean India Mission') was launched in 2014, its vision was both simple and transformative; to ensure that every household in India had access to a toilet. In just a decade, this vision has become reality. More than 12 crore household toilets have been built in rural India, and every village has declared itself Open Defecation Free (ODF). This achievement has improved public health, reduced indignities faced by women and vulnerable groups, and marked a turning point in India's development journey.

Focus on waste management

Yet, the success of the sanitation mission has also revealed the next frontier. Toilets are only the starting point. The real challenge lies in managing the resultant faecal waste. In most rural households, septic tanks and pits serve as the primary form of containment. Over time, these fill up and must be desludged at regular intervals. Without safe systems for collection, transport, and treatment, the gains of the ODF movement risk being undermined. It is this challenge that defines the transition to Swachh Bharat Mission (Grameen), or SBM-G, Phase II, with its focus on ODF Plus.

ODF Plus goes beyond toilet construction to ensure the sustainability of outcomes through solid and liquid waste management, behavioural change, and safe sanitation service chains. The progress has been encouraging. As of October 2025, more than 5.68 lakh villages, nearly 97% of India's total, have been declared ODF Plus. But faecal sludge management remains one of the most critical gaps in the sanitation chain, especially in peri-urban and rural areas.

Maharashtra has been at the forefront of

Aasim Mansuri

is Principal Researcher and Center Head-Strategy, Center for Water and Sanitation, CRDF-CEPT University

Dhruv Bhavsar

is Principal Researcher and Center Head, Center for Water and Sanitation, CRDF-CEPT University

Upasana Yadav

is Senior Program Lead, Center for Water and Sanitation, CRDF-CEPT University

Kasturi Joshi

is Program Lead, Center for Water and Sanitation, CRDF-CEPT University

Jinal Chheda

is Senior Research Associate, Center for Water and Sanitation, CRDF-CEPT University

The model in Satara district in Maharashtra is an innovative experiment

experimenting with innovative approaches to address this gap. The State has invested in more than 200 faecal sludge treatment plants in urban areas and encouraged co-treatment in 41 sewage treatment plants. These facilities are a backbone of treatment infrastructure to cities, but the challenge lies in extending their benefits to the villages that surround them. It is here that urban-rural partnerships show great promise.

At the gram panchayat level

In Satara district, Maharashtra, such a partnership was put into practice. Satara city's faecal sludge treatment plant, with a capacity of 65 kilo litres a day (KLD), was operating below full capacity. Recognising this, four villages, Jakatwadi, Songaon, Kodoli, and Degaon, have been brought under an arrangement that will allow them to access the city's treatment plant.

Their septic tanks, often never desludged or emptied only at exorbitant rates by informal operators, will be serviced at regular intervals and in a safe way. A private service provider is to be engaged by the gram panchayats, under a contract, to provide scheduled desludging services every five years.

The costs will be recovered through a modest sanitation tax levied by the gram panchayats, ensuring affordability and accountability. A formal agreement between the Satara Panchayat Samiti and the Satara Municipal Council will allow authorised desludging vehicles from the gram panchayats to access the faecal sludge treatment plant and treat the sludge at no cost, making the arrangement sustainable and mutually beneficial.

But not every village can be linked to a treatment system of a city. Some will have to treat

their waste independently. An example is Mayani, a large village in Khatav taluka. With the high demand for desludging services, the gram panchayat has agreed to introduce scheduled desludging every five to seven years, managed by either a private operator or local self-help groups.

In addition, Mayani has been selected for the development of a cluster-level faecal sludge treatment plant under the SBM-G, designed to serve around 80 surrounding villages. This approach shows that rural clusters can pool resources to develop standalone treatment infrastructure that meets their needs, while remaining financially and technically viable.

The demonstration of urban-rural linkages and the standalone faecal sludge management business model in Satara district will promote the adoption and the institutionalisation of safe, sustainable sanitation services across rural Maharashtra. It also aims to show that sustaining the gains of ODF and effectively integrating faecal sludge management into rural sanitation require strong collaboration between urban and rural governments, private and public actors, and citizens and institutions.

A model that can be scaled up

If scaled up, such models have the potential to transform not only villages in Maharashtra but also rural communities across the country. By doing so, India can ensure that its sanitation gains are not only celebrated today but can be sustained for generations to come. The true measure of Swachh Bharat will not only be the toilets built but also the systems created to manage them – systems that protect peoples' health, preserve the environment, and uphold the dignity that this mission set out to achieve.

GS Paper III: पर्यावरण

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न: अपशिष्ट-से-ऊर्जा और बायो-मिथेनेशन परियोजनाओं को अक्सर भारत की शहरी अपशिष्ट समस्या के समाधान के रूप में पेश किया जाता है। पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टिकोण से उनकी क्षमता और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। (150 शब्द)

संदर्भ :

तेजी से शहरीकरण ने अपशिष्ट प्रबंधन को भारत की सबसे गंभीर शासन और पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक बना दिया है। COP30 (बेलेम, 2025) में चर्चा, जिसने अपशिष्ट और चक्रीयता को जलवायु एजेंडे के केंद्र में रखा, वैश्विक मान्यता को पुष्ट करती है कि अपशिष्ट केवल स्वच्छता का मुद्दा नहीं है बल्कि जलवायु, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक चिंता है। मिशन लाइफ की भारत की अपनी वकालत और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का अनुभव शहरी कचरे को दायित्व के बजाय एक संसाधन के रूप में फिर से कल्पना करने के लिए एक मजबूत नीतिगत आधार प्रदान करता है।

मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डाला गया

शहरी अपशिष्ट का बढ़ता बोझ

- शहरी भारत में 2030 तक सालाना 165 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होने का अनुमान है, जो 2050 तक बढ़कर 436 मिलियन टन हो जाएगा।
- यह वृद्धि सीधे तौर पर मीथेन उत्सर्जन, वायु प्रदूषण, भूजल प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में योगदान देती है।

पारंपरिक अपशिष्ट प्रबंधन की सीमाएँ

- "कलेक्ट-डंप-बर्न" के रेखिक मॉडल पर्यावरण की दृष्टि से अस्थिर और वित्तीय रूप से अक्षम हैं।
- खुले में शौच को खत्म करने में उल्लेखनीय सफलताओं के बावजूद, डंपसाइट और खराब पृथक्करण स्वच्छता अभियान के तहत किए गए लाभ को नकार देते हैं।

प्लास्टिक और निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट

- प्लास्टिक कचरा पारिस्थितिक और स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है और गुणवत्ता और आर्थिक व्यवहार्यता के मुद्दों के कारण रीसाइक्लिंग बाजारों को चुनौती देता है।
- अनियोजित शहरी विस्तार के कारण सी एंड डी कचरा शहरों को अवरुद्ध करता है और मौजूदा नियमों के बावजूद खराब रूप से विनियमित रहता है।

अपशिष्ट जल और शहरी जल सुरक्षा

- उपचारित अपशिष्ट जल का अपर्याप्त पुनः उपयोग शहरी जल तनाव को बढ़ाता है।
- भविष्य की शहरी और औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए चक्रीय जल प्रबंधन आवश्यक है।

रणनीतिक समाधान के रूप में सर्कुलर इकोनॉमी

- लेख में सतत शहरीकरण के लिए एकमात्र व्यवहार्य दीर्घकालिक मार्ग के रूप में परिपत्रता को रेखांकित किया गया है:
- जैविक कचरे को विकेंद्रीकृत और बड़े पैमाने पर जैव-मिथेनेशन के माध्यम से खाद, बायोगैस और ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है।
- प्लास्टिक सहित सूखे कचरे के लिए मजबूत पृथक्करण, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं और प्रभावी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) ढांचे की आवश्यकता होती है।
- सी एंड डी कचरे को द्वितीयक निर्माण सामग्री में पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, जिससे पर्यावरणीय क्षति और इनपुट लागत कम हो जाती है।
- अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग स्वच्छता लक्ष्यों को जल सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन के साथ संरेखित करता है।
- कचरा मुक्त शहरों (जीएफसी) का लक्ष्य और सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी (सी-3) जैसी पहल शहरी सर्कुलरिटी के लिए एक उभरती हुई शासन संरचना का संकेत देती हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

- स्रोत पर कमजोर अलगाव और असंगत नागरिक भागीदारी
- सीमित नगरपालिका वित्त और तकनीकी क्षमता
- खराब अंतर-विभागीय समन्वय और नियमों का प्रवर्तन

- पुनर्नवीनीकरण उत्पादों के लिए बाजार, गुणवत्ता और विश्वास की कमी
- शहरी नियोजन और भवन नियमों के साथ सर्कुलरिटी का अधूरा एकीकरण

शासन और नीति अनिवार्यताएँ

- आगामी सी एंड डी अपशिष्ट नियमों सहित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रवर्तन को मजबूत करना।
- सूखे कचरे की सभी श्रेणियों में ईपीआर का विस्तार करें।
- रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी और नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- निगरानी, परीक्षण बुनियादी ढांचे और नगरपालिका क्षमता निर्माण में निवेश करें।
- प्रोत्साहन के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा दें, न कि केवल दंड के माध्यम से।

निष्कर्ष

कचरे से ग्रस्त शहरी भारत को बदलना शहरी सौंदर्यशास्त्र का विषय नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु शमन और आर्थिक स्थिरता के लिए एक अस्तित्वगत आवश्यकता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत भारत को पर्यावरणीय क्षरण से शहरी विकास को अलग करने के लिए एक यथार्थवादी मार्ग प्रदान करते हैं। मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय, नागरिक भागीदारी और बाजार समर्थन के साथ, अपशिष्ट शहरी विफलता के प्रतीक के बजाय हरित विकास का चालक बन सकता है। भारत के शहरों के लिए, चक्रीयता अब वैकल्पिक नहीं है - यह उनके भविष्य के लिए आधारभूत है।